डा० केसकर : अखबारों का सब से बड़ा सवाल हमारे सामने यह पेश था कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट की वजह से उन पर बड़ा भारी बोझा पड़ रहा है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट का सारा सवाल इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है। और जो अखबारों का खास दबाव था, हमारे सामने जो इनसिस्टेंस था, वह इस समय नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से इस मामले का जल्द से जल्द निर्णय करना चाहते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस के बारे में समाचारपत्र संम्पादक मंडली ने कोई प्रस्ताव पास किया है ?

डा० केसकर . एक प्रस्ताव उन की तरफ़ से हुआ है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हम सब मत-मतान्तर, जितने भी इस बारे में दिये जाते हैं, को ध्यान से देखते हैं, लेकिन इस में मुख्यतः जो अखबारों-समाचारपत्रों के मालिक हैं, उन्हीं से हमारी बात-चीत हो रही है, क्योंकि अखबार का जो मूल्य है, वह उसके मालिक ही तय करते हैं ।

Shri Ansar Harvani: Question No. 45 may be taken up along with Question No. 14.

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): That might be answered separately.

Mr. Speaker: Question No. 14 only may be answered now.

पोलैंड के साथ व्यापार

*१४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पोलैंड के बीच हुये व्यापार करार के फलस्वरूप व्यापार में किस हद तक वृद्धि होने की आशा है; और

(ख) पोलैंड को निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे के बदले में भारत में कितने मूल्य की किन-किन वस्तुओं का आयात होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) विदेशी व्यापार की उन्नति कई बातों पर निर्भर है और उस की वृद्धि करने के अनेक उपायों में इस प्रकार का करार केवल एक उपाय है। इस करार के पहले ही वर्ष यानी १९५६-५७ में भारत - पोलैंड व्यापार में पिछले साल की अपेक्षा आयात दस गुना और निर्यात चार गुना हुआ।

(ख) यह आवश्यक नहीं है कि कच्चे लोहे का निर्यात किन्हीं खास वस्तुओं के आयात के बदले में ही हो ।

Shri T. B. Vittal Rao: The answer may be read out in English.

Mr. Speaker: Yes.

Shri Satish Chandra: (a) Trade Agreement is only one of the means to facilitate foreign trade which is influenced by a number of factors. However, trade between India and Poland during the first year (1956-57) of the current Trade Agreeent increased ten times in the case of imports and four times in the case of exports over that of the previous year.

(b) Exports of iron ore are not necessarily tied up with imports of any specified goods.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि भारत में कच्चा माल भेजे जाने के बारे में जो करार हुआ है, क्या उसके अलावा और कोई माल भेजे जाने के बारे में तय हुआ है ? यदि हां, तो कौन सा माल ?

श्री सतीश चन्द्र : इस तरह के जो भी करार हुए हैं, उन की प्रतिलिपियां लाइब्रेरी में रख दी गई हैं। उस एग्रीमेंट के अनुसार ४३ चीजें ऐसी हैं, जिन को पोलैंड से इम्पोर्ट करने का हमारा इरादा था। ३८ आइटम्स एक्सपोर्ट के थे। इस में कुछ घटे और बढ़े भी हैं। अब

१६ आइटम्ज इम्पोर्ट के और ५० आइटम्ज एक्सपोर्ट के हैं। इन की कुल लिस्ट देना इस वक्त मुश्किल है।

श्री ब० ला० द्विवेदी : इस व्यापार के भुगतान का तरीका क्या है—क्या विनिमय भारतीय सिक्के में है या किसी और सिक्के में ? यदि किसी और सिक्के में है, तो किस सिक्के में?

श्री मनीषा चन्द्र : करार के मुताबिक यह पेमेंट रुपये में होता है, लेकिन क्योंकि अभी बैलेंस आफ़ पेमेंट का संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए कुछ पेमेंट स्टरलिंग में भी करना पड़ता है। इसी महीने पोलैंड से एक डैलीगेशन इस बात पर विचार करने के लिए आ रहा है कि किस तरह हम इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं।

Shri Khadilkar: May I know in these items if there is sugar plant machinery and if so, whether some machinery has been imported under the terms of the agreement?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): Sugar plants are not included in this bilateral agreement.

Shri Ansar Harvani: Is it not a fact that the State Trading Corporation received a huge amount of trade enquiries from Poland and only a fraction was satisfied?

The Minister of Commerce (Shri Kanungo): That is Question No. 45.

Shri T. K. Chaudhuri: May I know what are the imported items in which increase has been registered?

Shri Satish Chandra: There has been substantial increase in the imports of iron and steel and machinery.

Indo-Pakistan Agreement on Movable Property

*15. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of Rehabilitation and Minority Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 697 on the 2nd December, 1957 and state further progress, if any, made in the implementation of the Indo-Pakistan Agreement on movable property?

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): Bank Drafts for Rs. 5·22 lacs and some lists of movable property were received from Pakistan in January, 1958.

A further exchange of fire-arms will be held on February 24, 1958. Exchange of further lists of Post Office Savings Bank Accounts and Postal Certificates will start on the 1st March, 1958. Supplementary lists of movable property, bank drafts for sale-proceeds and further lists of court deposits and lockers and safe deposits will be exchanged on March 25/26, 1958. The transfer of lockers and safe deposits would follow soon thereafter.

Shri D. C. Sharma: May I know on how many items there has been agreement so far as movable property is concerned and on how many items there has been no agreement so far and the Minister is making efforts to bring about agreement?

Shri Mehr Chand Khanna: There has been agreement practically on almost all items. The difficulty has been about implementation and we are trying to expedite matters.

Shri D. C. Sharma: May I know what efforts have been made to strengthen the machinery for implementation both in Pakistan and India?

Shri Mehr Chand Khanna: When I visited Karachi about two years ago with a view to see that the agreement is properly implemented, an Implementation Committee was set up between India and Pakistan. The meetings of this Committee are not held regularly. We want them to be held frequently, but sometimes we do not find the same responsive co-operation from the other side.

Shri Ajit Singh Sarhadi: May I know whether the agreement also covers those who have vacated the so-called Azad Kashmir territory?